(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा क्रियान्वयन समिति में पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मिलित किया गया है ;

(ख) क्या हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियों का गठन हो चुका है तथा सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा हिन्दी में किये गये कार्य का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) हिन्दी सलाहकार समिति की कोई उप-समितियां नहीं बनाई गई हैं ।

मंत्रालय तथा इसके विभागों, निगमों, आदि में हिन्दी में किये गये कार्य का निरीक्षण इस प्रयोजन के लिये बनाये गये अधिकारियों के राजभाषा निरीक्षण दलों द्वारा किया जा रहा है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये मंत्रालय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षकों के रूप में गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किये जाने तथा हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियों के गठन किये जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की है ।

**वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति**

200. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमानुसार गत वर्ष हिन्दी सलाहकार समिति की चार बैठकें बुलाई गईं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय पिछले पांच वर्षों से योजना के अनुसार हिंदी के वार्षिक कार्यक्रम को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर रहा है और इस प्रकार, हिंदी के प्रयोग के मामले में कोई प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षकों के रूप में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति-विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर)** : (क) और (ख) गत वर्ष कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों की वजह से समिति की चार बैठकें नहीं की जा सकीं । वार्षिक हिन्दी कार्यक्रम के पूर्ण अनुपालन के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं । हिन्दी के प्रयोग के मामले में, सरकारी कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की गई है ।

(ग) चूंकि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, अतः राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कोई गैरसरकारी सदस्य शामिल नहीं किया गया है ।

**हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का बुलाया जाना**

201. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष नियमानुसार मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की चार

बैठकें न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों को राज भाषा क्रियान्वयन समितियों में पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उसने गत वर्ष मंत्रालय के अधीन कितने कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा शेष कार्यालयों का निरीक्षण कब तक पूरा हो जायेगा, और

(घ) क्या यह सच है कि विभाग पिछले पांच वर्षों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव)** : (क) पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकें हुई हैं । चौथी बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका ।

(ख) रक्षा मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में एक गैर-सरकारी सदस्य प्रेक्षक के रूप में पहले से ही नामित है ।

(ग) वर्ष 1983–84 के दौरान रक्षा मंत्रालय के अधीन 101 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । अन्य कार्यालयों/यूनिटों का निरीक्षण यथाशीघ्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) रक्षा मंत्रालय के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में तैयार किये गये वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कुछ कमियां रह गई हैं । निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

**Inei-MM in Demand of SM Shells Io U.S.A., Europe and Japan**

202. SHRI M. BASAVARAJU; Will the Minister of COMMERCE be' pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Statesmant of 29th May, 1984 to the effect that Sea Shells were one of the hottest export items and demand for the same has increase^ in USA, Europe and Japan; and

(b). if so, what steps Government propose to take with a view to make a dent in the international market for the said item in a big way?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OS SUPPLY (SHR NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Yes, Sir.

(b) Sea Shells constitute less than one percent of the Indian exports of marine products. No special measures have been taken to boost the exports of this commodity, but exports of marine products including sea-shells benefit from the Trade Promotion Offices of the Marine Products Export Development Authority tn Japan and USA, participation In trade fairs, advertisements in leading journals in important markets, exchange of delegations etc.

**. Tourism Publicity Material on Mahatma Gandhi**

203. SHRI M. BASAVARAJU: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have prepared publicity material on Mahatma Gandhi for use in overseas tourist offices to promote tourism in view of the success of the film 'Gandhi'; and

(b) if so, the extent to which the same has helped in promoting foreign tourism?